



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012020-215616  
CG-DL-E-21012020-215616

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]  
No. 18]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2020/पौष 30, 1941  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2020/PAUSAH 30, 1941

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

(मामला संख्या ओआई-31/2019)

**विषय:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हॉगकॉंग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेज़ न्यूज़प्रिंट" को छोड़कर, रोलों अथवा शीटों में न्यूज़प्रिंट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा.सं. 6/40/2019-डीजीटीआर.—1.** इंडियन न्यूज़प्रिंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हॉगकॉंग, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेज़ न्यूज़प्रिंट" को छोड़कर, रोलों अथवा शीटों में न्यूज़प्रिंट (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों के

संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क की जांच के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया है।

### संबद्ध देश

- आवेदक ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हाँगकाँग, कोरिया गणराज्य, रूस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से पाटन और क्षति का दावा किया है। तथापि, डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य से आयातों का पहुँच मूल्य दर्शाता है कि क्षति मार्जिन नकारात्मक है। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हाँगकाँग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

### विचाराधीन उत्पाद

- विचाराधीन उत्पाद ग्लेज़ न्यूज़प्रिंट को छोड़कर, रोलों अथवा शीटों में न्यूज़प्रिंट है।
- न्यूज़प्रिंट एक प्रकार का अनकोटेड पेपर है जिसका प्रयोग समाचार पत्रों के मुद्रण के लिये किया जाता है जिसमें कुल फाइबर तत्व के 50 प्रतिशत से अनधिक भार में यांत्रिक अथवा रासायनिक-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त बुड़ फाइबर होता है जिसका कि आकार नहीं होता अथवा बहुत हल्का आकार होता है और जिसमें 2.5 माइक्रोमीटर से अधिक प्रत्येक ओर पर सरफेस रफ्नेस पार्कर प्रिंट सर्फ (1 एमपीए) होता है और जिसका वजन 40 ग्राम/एम<sup>2</sup> से कम नहीं होता तथा 65 ग्राम/एम<sup>2</sup> से अधिक नहीं होता और;
- क. 28 से.मी. से अधिक की चौड़ाई के स्ट्रिप अथवा रोल में; अथवा
- ख. एक ओर 28 से.मी. से अधिक और दूसरी ओर 15 से.मी. से अधिक फोल्ड न की हुई स्थिति में आयताकार (वर्ग सहित) शीटों में।
- विचाराधीन उत्पाद को किलोग्राम में अथवा मीट्रिक टन में व्यक्त भार अथवा वर्ग मीटर के रूप में व्यक्त क्षेत्र के संबंध में भी बताया जा सकता है। जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए आंकड़ों पर मीट्रिक टन में भार द्वारा बताये गये पर विचार किया गया है।
- विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण 4801 00 90 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद कोड 4801 00 10 के तहत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

- आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। पाटित आयातों की तकनीकी विशिष्टियों, गुणवत्ता, प्रकार्य और अंतिम प्रयोगों तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित घरेलू रूप से उत्पादित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए पाटनरोधी नियमावली के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पादों की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

### घरेलू उद्योग

- यह आवेदन पत्र समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों की ओर से इंडियन न्यूज़प्रिंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन पत्र का समर्थन समान वस्तुओं के 17 अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है और किसी भी घरेलू उत्पादक द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में

विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातिक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम 2(ब) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

### आरोपित पाटन का आधार सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने उल्लेख किया है कि घरेलू उत्पादक समान वस्तु का विनिर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में रिसाइकिल्ड अथवा वेस्ट पेपर का प्रयोग करते हैं जबकि अधिकतर विदेशी उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में बुड़ पल्प का प्रयोग करते हैं और बुड़ पल्प से परिवर्तन लागत रिसाइकिल पेपर से परिवर्तन लागत के कम से कम तीन गुना है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनबी) पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
10. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क में उल्लेख है कि किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अभिप्राय निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए निर्दिष्ट होने पर समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत है। यूरोपीय संघ में आवेदक ने घरेलू बिक्री कीमत के निर्धारण के लिए अतः यूरोपीय संघ व्यापार अंकड़ों पर विश्वास किया है। इसी प्रकार, कनाडा के मामले में आवेदक ने घरेलू बिक्री कीमत के निर्धारण के लिए प्रकाशित रिपोर्टों पर विश्वास किया है। तथापि, अन्य देशों के लिए घरेलू बिक्री कीमत उपलब्ध न होने का दावा किया गया है और इसीलिए आवेदक ने उस देश में विचाराधीन देश के आयात अंकड़ों पर विश्वास किया है। तदनुसार, जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा निर्मित सामान्य मूल्य से कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

### निर्यात कीमत

11. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात अंकड़ों के आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजन किए गए हैं।
12. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी पाटन मार्जिन दर्शाती है। इसका पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

### क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

13. घरेलू उद्योग को क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण प्रभाव, भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसका निष्पादन उत्पादन, बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह में गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग के लिए बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही है।

### पाटनरोधी जांच की शुरूआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा और घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत पूर्ण लिखित आवेदन पत्र के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत

प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को क्षति तथा तथाकथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और जो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

### जांच की अवधि (पीओआई)

15. आवेदक ने जांच अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई भी कहा गया है) 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) प्रस्तावित की, परंतु प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 माह) प्रस्तावित की। क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि शामिल होगी।

### प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांत अपनाए जाएंगे।

### सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें।
18. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएः:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**व्यापार उपचार महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**भारत सरकार**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001**

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

### समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपर्युक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो

प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समझ कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

- गोपनीय चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची, आदि)
- अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची, आदि)।

23. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

24. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

25. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानत: उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपर्युक्त समझ देने के लिए पर्याप्त व्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

26. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

27. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

28. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल की निरीक्षण

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

## असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### Department of Commerce

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2020

(Case No.OI-31/2019)

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint” originating in or exported from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and United Arab Emirates.**

**F.No.6/40/2019-DGTR.**—1. Indian Newsprint Manufacturers Association (hereinafter referred to as the “Applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for original anti-dumping duty investigation on imports of “Newsprint, in rolls or sheets, excluding glazed newsprint” (hereinafter referred as “product under consideration” or PUC or “subject goods”) originating in or exported from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Korea RP, New Zealand, Russia, Singapore and United Arab Emirates.

#### Subject Countries

2. The Applicant has claimed dumping and injury from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Korea RP, Russia, Singapore, New Zealand and United Arab Emirates. However, landed value of imports from New Zealand & Korea RP based on DGCI&S import data indicates that injury margin is negative. Accordingly, the subject countries for the present investigation are Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and United Arab Emirates.

#### Product under consideration

3. The product under consideration is newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint.

4. Newsprint is an uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 50% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 Mpa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m<sup>2</sup> and not more than 65 g/m<sup>2</sup> and;

- a. in strips or rolls of a width exceeding 28 cm; or
- b. in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 28 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state.

5. The PUC may be denominated in terms of area expressed as square metre or weight expressed in kgs or MT. For the purpose of initiation, the data has been considered as denominated by weight in MT.

6. The PUC is classified under the tariff custom classification 4801 00 90. The PUC, however, has been imported under the code 4801 00 10 also. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

#### **Like article**

7. The Applicant has claimed that the PUC, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced goods manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, the goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the PUC being imported from the subject countries.

#### **Domestic industry**

8. The application has been filed by the Indian Newsprint Manufactures Association on behalf of the domestic producers of the like articles. The application has been supported by 17 other domestic producers of like articles and has not been opposed by any domestic producer. The Applicant has claimed that neither they have imported the PUC from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

#### **Basis of alleged dumping**

##### **Normal Value**

9. The Applicant has stated that the domestic producers use recycled or waste paper as the raw material for manufacturing the like article, while most of the foreign producers use wood pulp as raw material for producing the PUC and the conversion cost from wood pulp is at least three times the conversion cost from recycled paper. The Applicant has, therefore, requested that Constructed Normal Value (CNV) on the basis of cost of production in India should not be considered for determination of normal value.

10. Section 9A of the Customs Tariff Act states that the normal value in relation to an article means the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory. In case of European Union, the Applicant has relied on the intra-EU trade data for determination of domestic selling price. Similarly, in case of Canada the Applicant has relied upon published reports for determination of domestic selling price. However, for other countries domestic selling price has been claimed to be not available and therefore the Applicant has relied on the import data of the PUC into that country. Accordingly, the Authority for the purpose of initiation, decided to proceed with the normal value as constructed by the Applicant.

#### **Export price**

11. The Authority has computed the export price for all the subject countries based on DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission and inland freight.

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows significant dumping margin in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient *prima facie* evidence that the PUC are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

#### **Injury and Causal link**

13. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the

domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of PUC at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

**Initiation of Anti-Dumping Investigation**

14. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Period of Investigation (POI)**

15. The Applicant proposed the Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) 01<sup>st</sup> April, 2019 – 31<sup>st</sup> September, 2019 (6 months). However, the Authority has proposed the POI in the present investigation as 01<sup>st</sup> April 2019 – 31<sup>st</sup> December 2019 (9 months). The injury investigation period will cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.

**Procedure**

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**Submission of Information**

17. The known exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

**The Designated Authority**

**Directorate General of Trade Remedies**

**Ministry of Commerce & Industry**

**Department of Commerce**

**Government of India**

**4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street**

**New Delhi-110001**

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**Submission of information on confidential basis**

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

29. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority